



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4008]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 9, 2018/आश्विन 17, 1940

No. 4008]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 9, 2018/ASVINA 17, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

आदेश

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर, 2018

आय-कर

का.आ.5194(अ).—बेनामी संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988 (1988 का 45) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 48 की उपधारा (1) उपबंध करती है कि कोई व्यक्ति जिसने उक्त अधिनियम के अधीन किसी अपील अधिकरण के समक्ष कोई अपील की है, अपील अधिकरण के समक्ष अपना पक्षकथन पेश करने के लिए या तो स्वयं उपस्थित हो सकेगा या अपने विकल्प के किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि की सहायता ले सकेगा; उक्त अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (2) उपबंध करती है कि केन्द्रीय सरकार अपने अधिकारियों में से एक या अधिक को उपस्थान अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी, और इस प्रकार प्राधिकृत प्रत्येक व्यक्ति अपील अधिकरण के समक्ष किसी अपील के सम्बन्ध में पक्षकथन पेश कर सकेगा; उक्त अधिनियम की धारा 48 का स्पष्टीकरण उक्त धारा के उद्देश्यों के लिए “प्राधिकृत प्रतिनिधि” पदों को परिभाषित करता है;

और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए ऐसी कठिनाई उद्भूत हुई है कि, उक्त अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (1) के अधीन,-

- प्रारंभिक अधिकारी, व्यक्ति होते हुए उक्त अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण के समक्ष अपील की है, या तो वह स्वयं उपस्थित हो सकेगा या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि की सहायता ले सकेगा, उक्त अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (1) में प्रारंभिक अधिकारी के विनिर्दिष्ट निर्देश की अनुपस्थिति से उत्पन्न कठिनाई को दूर करने की आवश्यकता है; और
- अपील करने वाले व्यक्ति के लिए अपील अधिकरण के समक्ष प्रतिनिधित्व करने के लिए उपबंध करता है, किन्तु अपील अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों को करने के लिए अन्य पक्षकारों द्वारा प्रतिनिधित्व करने का उपबंध नहीं करता है, अपील अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों को करने के लिए अन्य पक्षकारों द्वारा प्रतिनिधित्व करने के सम्बन्ध में कठिनाईयों को दूर करने की आवश्यकता है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 70 की उपधारा (1) का प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में पूर्वोक्त कठिनाईयों को हटाने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-** (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम बेनामी संव्यवहार प्रतिषेध (कठिनाईयों को दूर करना) आदेश, 2018 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. बेनामी संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988 की धारा 48 में,-

(क) उपधारा (1) में “कोई व्यक्ति जिसने उक्त अधिनियम के अधीन किसी अपील अधिकरण के समक्ष कोई अपील की है” शब्दों के स्थान पर “कोई व्यक्ति, जिसके अन्तर्गत प्रारंभिक अधिकारी भी हैं, जो उक्त अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण के समक्ष किन्हीं कार्रवाईयों का पक्षकार है” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) स्पष्टीकरण में,-

(I) प्रारंभिक भाग में “प्राधिकृत प्रतिनिधि से अपीलार्थी द्वारा इस निमित्त हाजिर होने के लिए लिखित में कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है” शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“प्राधिकृत प्रतिनिधि से –

(i) प्रारंभिक अधिकारी के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(ii) कार्रवाईयों के किसी अन्य पक्षकार के सम्बन्ध में, से पक्षकार द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(II) खंड (i) और खंड (ii) में, “अपीलार्थी” शब्दों के स्थान पर जहां कहीं वे आते हैं, के सम्बन्ध में “पक्षकार” शब्द रखा जाएगा।

[फा. सं. 370149/170/2018-टीपीएल]

प्रवीण रावल, निदेशक (टीपीएल-II)

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

ORDER

New Delhi, the 9th October, 2018

INCOME-TAX

S.O.5194 (E).—Whereas, sub-section (1) of section 48 of the Prohibition of Benami Property Transactions Act, 1988 (45 of 1988) (hereafter referred to as the said Act) provides that a person preferring an appeal to the Appellate Tribunal under said Act may either appear in person or take the assistance of an authorised representative of his choice to present his case before the Appellate Tribunal; sub-section (2) of section 48 of the said Act provides that the Central Government may authorise one or more of its officers to act as presenting officers on its behalf, and every person so authorised may present the case with respect to any appeal before the Appellate Tribunal; the *Explanation* to section 48 of the said Act defines the term “authorised representative” for the purposes of said section;

And, whereas, a difficulty has arisen in view of the fact that although, under sub-section (1) of section 48 of the said Act—

(i) the Initiating Officer, being a person preferring appeal to the Appellate Tribunal under the said Act, may either appear in person or take the assistance of an authorised representative, there is a need to remove the difficulty arising from the absence of specific reference of the Initiating Officer in sub-section (1) of section 48 of the said Act; and

(ii) provides for the representation before the Appellate Tribunal for the person preferring appeal, but does not provide for representation by the other parties to the proceedings before the Appellate Tribunal, there is a need to remove difficulty in respect of representation by the other parties to the proceedings before the Appellate Tribunal;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 70 of the said Act, the Central Government hereby makes the following Order to remove the aforesaid difficulties, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) This Order may be called the Prohibition of *Benami* Property Transactions (Removal of Difficulties) Order, 2018.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In section 48 of the Prohibition of *Benami* Property Transactions Act, 1988, —

(A) in sub-section (1), for the words “A person preferring an appeal to”, the words “A person, including the Initiating Officer, who is a party to any proceedings before” shall be substituted;

(B) in the *Explanation*, —

(I) in the opening portion, for the words “means a person authorised by the appellant” the following shall be substituted, namely: —

“in relation to —

- (i) the Initiating Officer, means a person authorised by the Central Government;
- (ii) any other party to the proceedings, means a person authorised by the party”;

(II) in clause (i) and (ii) for the words, “the appellant” wherever they occur, the words “the party” shall be substituted.

[F. No.370149/170/2018-TPL]

PRAVIN RAWAL, Director (TPL-II)